EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

Useful For Prelims

Date: 7 - 11 - 2025

बिहार में 27 वर्ष बाद बंपर वोटिंग, पहले चरण में 64.66 % मतदान

18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने 1314 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में किए बंद

महासमर बिहार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

1314 प्रत्याशियों में 1192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी, सम्राट, विजय और तेजस्वी के भाग्य भी ईवीएम में

2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में सात प्रतिशत अधिक लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग

लखीसराय समेत कई जिलों में स्थानीय समस्याओं से नाराजगी के कारण कुछ लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार

बेगूसराय, समस्तीपुर एवं मधेपुरा में सर्वाधिक तो शेखपुरा में सबसे कम लोग घरों से मतदान के लिए निकले

2020 विधानसभा चुनाव में पड़े थे 57.29 % लोकसभा चुनाव 2024 में पड़े थे 56.28% वोट

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। लगभग 64.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही सर्वाधिक मतदान का रिकार्ड भी बन गया। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 27 वर्ष बाद इतनी अधिक संख्या में मतदाताओं की सहभागिता देखने को मिली। इसके पूर्व वर्ष 1998 में 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ था।

उधर, 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में सात प्रतिशत अधिक एवं लोकसभा चुनाव 2024 की तुलना में लगभग आठ प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने अबकी बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 59.29 एवं 2024 के लोकसभा चुनाव में 56.28 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार सर्वाधिक वोट बेगूसराय में 70 प्रतिशत, समस्तीपुर में 68 एवं मधेपुरा 67 प्रतिशत डाले गए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक सहभागिता रही। आयोग की ओर से सभी 45,341 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रथम चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने 1314 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया। कुल 1314 प्रत्याशियों में 1192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी हैं। प्रथम चरण में उप मुख्यमंत्रीद्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत सरकार के कई मंत्रियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के राघोपुर क्षेत्र में भी वोट डाले गए। लखीसराय समेत कई जिलों में पक्ष-विपक्ष के बीच मामूली नोकझोंक की सूचना है। उपमुख्यमंत्री व लखीसराय से भाजपा प्रत्याशी विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि एक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। वहीं, कुछ जिलों में लोगों ने स्थानीय समस्याओं को लेकर कुछ बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया।

पटना में गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के लिए एक केंद्र के बाहर कतार में खड़े मतदाता। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। एएनआइ

बंपर वोटिंग के तीन प्रमुख कारण : पहला व मुख्य कारण दीवाली एवं छठ में विभिन्न राज्यों में प्रवास करने वाले मतदाताओं के लिए दीवाली एवं छठ पर 13 हजार से अधिक ट्रेनें चलाना एवं आए हुए लोगों का मतदान के लिए रुकना। दूसरा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण(एसआइआर) और तीसरा सरकार की ओर से दिए जा रहे 10-10 हजार रुपये का प्रभाव भी माना जा रहा है।

(पेज-4 भी देखें)

भाजपा अध्यक्ष नड्डा का साक्षात्कार: जंगलराज विकास का सबसे बड़ा विरोधी पेज>>5

Dainik jaagaran Page No-1

सहंसरा नदी किनारे मिला छह करोड़ साल पुराना जीवाश्म

जीवाश्म की पहचान ट्राइसेराटाप्स डायनासोर की नाक के सींग के रूप में हुई

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

शिवालिक क्षेत्र में सहंसरा नदी किनारे करीब साढ़े छह करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। इसकी खोज पर्यावरण विज्ञानी डा. उमर सैफ ने की है। उन्होंने बताया कि नदी किनारे मिले सींग के जीवाश्म की पहचान ट्राइसेराटाप्स डायनासोर की नाक के सींग के रूप में हुई है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र से डायनासोर के पंख और अंडे के जीवाश्म मिल चुके हैं।

देहरादून के हिमालयन एन्वायरनमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक डा. उमर सैफ ने बताया कि शिवालिक क्षेत्र की सहंसरा नदी की घाटी में पाए जाने वाली अवसादी चट्टानें लेट क्रेटेशियस काल (करीब 10 करोड़ साल से छह करोड़ साल पहले तक) की परतों से मेल खाती हैं। बीते एक अक्टूबर को ग्राम कोठरी, बहलोलपुर में सहंसरा नदी के तट पर उन्होंने महत्वपूर्ण जीवाश्म की खोज की है। यह संभवतः साढ़े छह करोड़ साल से ज्यादा पुराना व किसी सींगधारी डायनासोर की नाक का सींग हो सकता है। डा. सैफ ने बताया कि लाखों साल तक पानी के संपर्क में रहने व भारी खनिजीकरण (मिनरलाइजेशन) के कारण जीवाश्म पूरी तरह से सैंडस्टोन में परिवर्तित हो चुका है।

जीवाश्म की विशेषता : डा. सैफ ने बताया कि जीवाश्म की लंबाई 330 मिमी, बीच में से मोटाई 55 मिमी है। आकार दोधारी कटार जैसा है। यह ट्राइसेराटाप्स डायनासोर की नाक के सींग से मिलता-जुलता है। जीवाश्म सैंड कास्ट में परिवर्तित हालत में मिला। कोशिकीय स्तर पर मिनरलाइजेशन हो चुका है।

सहारनपुर में सहंसरा नदी किनारे मिला जीवाश्म। सौ. वातावरण विज्ञानी

पहले भी मिल चुके हैं सहंसरा किनारे जीवाश्म

इस क्षेत्र में पहले में भी उत्तरी क्रेटेशियस काल के अन्य जीवाश्म मिल चुके है। ऐसे में यह स्थान पुराजैविक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। सहंसरा नदी के किनारे की भूगर्भीय संरचना और जलवायु ने भी जीवाश्मों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पुराजैविक विशेषज्ञों, भूवैज्ञानिकों और संबंधित संस्थानों से भी इस खोज की वैज्ञानिक पुष्टि और अध्ययन के लिए इस क्षेत्र का दौरा करने का आग्रह किया। यह खोज भारत के डायनासोर इतिहास को पुनर्परिभाषित करने में मदद कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में स्नेकहेड मछली की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा

जागरण संवाददाता, सोलन

हिमाचल प्रदेश के कसौली के भूविज्ञानी डा. रितेश आर्या ने करीब 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी स्नेकहेड मछली की खोपड़ी के जीवाश्म की खोज की है। इससे मीठे पानी की मछलियों के विकास व टेथिस सागर के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में नई दिशा मिलेगी।

जीवाश्म की पहचान पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के भूविज्ञान विभाग के प्रो. राजीव पटनायक ने स्नेकहेड फिश के रूप में की, जो चैनिडे फिश परिवार से संबंधित है। वरिष्ठ विज्ञानी एवं कशेरुकी जीवाश्म विशेषज्ञ प्रो. अशोक सहनी ने कहा कि पहले भी सुबाथू से मछलियों के जीवाश्मों की सूचना मिली है, लेकिन डा. आर्या की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुबाथू के नजदीक स्नेकहेड मछली की खोपड़ी का जीवाश्म। सौ. डॉ. रितेश आर्या

Dainik Jagaran Page No-14

‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष

स्मारक डाक टिकट व सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज 7 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मारक डाक टिकट व सिक्का जारी करेंगे। यह कार्यक्रम सालभर यानि 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा ताकि भारतवासी इस कालजयी रचना के 150 साल पूरे होने का जश्न मना सकें।

बता दें कि इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े 9 बजे ‘वंदे मातरम’ के वर्षभर चलने वाले समारोह का

प्रधानमंत्री ‘वंदे मातरम’ के वर्षभर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे।

उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में समाज के सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी के साथ, सुबह लगभग 9:50 बजे ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जाएगा। मालूम हो कि 7 नवंबर, 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की रचना की थी। ‘वंदे मातरम’ पहली बार साहित्यिक पत्रिका ‘बंगदर्शन’ में चटर्जी के उपन्यास ‘आनंदमठ’ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसे लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने गुरुवार को एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया।

संस्कृति मंत्री ने बताया कि शुक्रवार को आयोजित समारोह के दौरान ‘नाद एकम, रूपम अनेकम’ के नाम से वायलिन वादक डा मंजूनाथ मैसूर की ओर से संचालित लगभग 75 संगीतकारों के साथ प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही ‘वंदे मातरम’ के 150 साल के इतिहास पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय व विभाग और उनसे जुड़े अधीनस्थ कार्यालय 7 नवंबर को अपने कार्यालय परिसर में ‘वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

Jansatta Page No-16

वैश्विक स्तर के बैंकों की आवश्यकता

मुंबई, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश

को बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत है और इस संबंध मे आरबीआई के साथ बातचीत जारी है।

सीतारमण ने 12वें ‘एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनमिक्स’ सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया।

अमेरिका से वार्ता जारी, जल्द होगा समझौता

सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच यह वार्ता अब अंतिम चरण मे पहुंच चुकी है और सरकार इसका जल्द निष्कर्ष चाहती है।

कर्मी का स्थानीय भाषा जानना सुनिश्चित करें

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए शाखा कर्मचारियों के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी सुनिश्चित करें। स्थानीय भाषा न बोलने पर बैंक कर्मियों के राजनीतिक दलों के गुस्से का सामना करने की घटनाओं के बाद उन्होंने यह बात कही है।

उन्होंने कहा, सरकार वायदा एवं विकल्प कारोबार मे खुदरा निवेशकों को शामिल होने नहीं से नहीं रोक सकती, लेकिन ऐसे उत्पादों मे पैसा लगाने से जुड़े जोखिमों के बारे मे जागरूक जरूर करेगी।

Hindustan Page No-15

दुनिया में जल संकट और सूखा सबसे बड़ी चिंता

नई दिल्ली, एजेंसी। जल की कमी और सूखा दुनियाभर में लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में लोग सबसे अधिक लोग इससे चिंतित है। प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से भारत सहित 9 देशों में किए गए सर्वे से यह खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट बताती है कि 47 फीसदी लोगों ने सूखे या जल की कमी को अन्य खतरों की तुलना में दोगुना बड़ा खतरा बताया। बहुत कम लोगों ने कहा कि गर्म मौसम, बाढ़ या तूफान, या समुद्र का बढ़ता स्तर खतरे हैं। 2015 के बाद से, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में सूखे को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताने वालों की संख्या बढ़ी है।

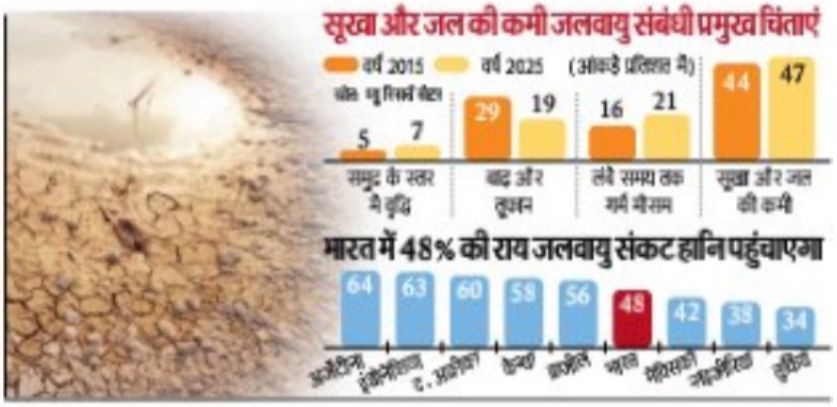

56 फीसदी लोग पीड़ित: भारत सहित 9 देशों में 56% वयस्कों ने यह चिंता जताई कि जलवायु परिवर्तन उन्हें व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाएगा। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में लगभग दस में से छह या उससे अधिक लोग यह मानते है, तुर्की में यह लगभग एक तिहाई है।

Hindustan Page No-16

Useful For Mains

राष्ट्र जागरण का प्रथम मंत्र वंदे मातरम्

अमित शाह

औपनिवेशिक भारत के सबसे अंधकारमय काल में लिखा गया वंदे मातरम् जागृति का एक ऐसा प्रभात-गीत बन गया, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सभ्यतागत गौरव के साथ जोड़ दिया

हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जब गीतों, कलाओं ने अलग-अलग रूपों में लोक भावनाओं को सहेजकर आंदोलन को आकार देने में महती भूमिका निभाई। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना के युद्धगीत हों, आजादी के आंदोलन में सेनानियों के गान हों या आपातकाल के विरुद्ध युवाओं के सामूहिक गीत, इन सबने भारतीय समाज को स्वाभिमान की प्रेरणा भी दी और एकजुट भी किया। ऐसा ही है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्, जिसका इतिहास किसी युद्धभूमि से नहीं, बल्कि विद्वान बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी के शांत, लेकिन अडिग संकल्प से शुरू होता है। 1875 में जगद्धात्री पूजा (कार्तिक शुक्ल नवमी या अक्षय नवमी) के दिन उन्होंने उस स्रोत की रचना की, जो भारत की स्वतंत्रता का शाश्वत गीत बन गया। इन पवित्र शब्दों को लिखते हुए वे भारत की गहनतम सभ्यतागत जड़ों से प्रेरणा ले रहे थे। अथर्ववेद के उद्घोष 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' से लेकर देवी महात्म्य में विश्वमाता के आह्वान से प्रेरणा ले रहे थे।

बंकिम बाबू का यह मंत्र प्रार्थना भी था और भविष्यवाणी भी। वंदे मातरम् केवल भारत का राष्ट्रीय गीत ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण ही नहीं, बल्कि यह बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रथम उद्घोषणा है। इसने हमें याद दिलाया कि भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक भू-सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसकी एकता उसकी संस्कृति और सभ्यता से आती है। यह केवल भू-भाग नहीं है, बल्कि तीर्थ है, स्मृति, त्याग, शौर्य और मातृत्व से बंधी पवित्र भूमि है। जैसा कि महर्षि अरबिंद ने वर्णन किया, बंकिम आधुनिक भारत के एक ऋषि थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्र के आत्मा को पुनर्जीवित किया। उनका आनंदमठ केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि गद्य में एक मंत्र था, जिसने एक ऐसे राष्ट्र को जागृत किया, जो अपनी दिव्य शक्ति को भूल चुका था। अपने एक पत्र में बंकिम बाबू ने लिखा, 'मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि मेरे सभी कार्य गंगा में बहा दिए जाएं। यह श्लोक ही अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा।' ये शब्द भविष्यसूचक थे। औपनिवेशिक भारत के सबसे अंधकारमय काल में लिखा गया वंदे मातरम् जागृति का प्रभात-गीत बन गया, एक ऐसी रचना, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सभ्यतागत गौरव के साथ जोड़ दिया। ऐसी पंक्तियां केवल वही व्यक्ति लिख सकता था, जिसके रोम-रोम में राष्ट्र के प्रति भक्तिभाव कूट-कूट कर भरा हो।

अवधेश राजपूत

वर्ष 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम् को धुन में पिरोया और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया, जिससे इसे वाणी और अमरता प्राप्त हुई। यह गीत भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में गूंज उठा। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने इसका तमिल अनुवाद किया और पंजाब में क्रांतिकारियों ने इसे गाते हुए ब्रिटिश राज को खुली चुनौती दी। 1905 में बंग-भंग आंदोलन के दौरान बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेजों ने वंदे मातरम्' के सार्वजनिक पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी 14 अप्रैल, 1906 को बारीसाल में हजारों लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की। जब पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर लाठीचार्ज किया तो पुरुष और महिलाएं सड़कों पर वंदे मातरम् का नारा लगाते हुए लहूलुहान हो गए। वहां से 'वंदे मातरम् का मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफोर्निया पहुंच गया। यह आजाद हिंद फौज में भी गूंजा, जब नेताजी के सैनिक सिंगापुर से मार्च कर रहे थे। इसी तरह यह 1946 में रायल इंडियन नेवी की क्रांति में भी गूंजा, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। खुदीराम बोस से लेकर अशफाक उल्ला खां तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तिरुपुर कुमारन तक, नारा एक ही था। यह अब केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि भारत के सामूहिक आत्मा की आवाज बन गया। महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि वंदे मातरम् में "सबसे सुस्त रक्त को भी जगाने की जादुई शक्ति" थी। इसने उदारवादियों और क्रांतिकारियों तथा विद्वानों और नाविकों तक को एकजुट किया। महर्षि अरबिंद जी ने इसीलिए कहा था कि यह 'भारत के पुनर्जन्म का मंत्र' है।

26 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंदे मातरम् गीत के इस इतिहास को देशवासियों को फिर से याद दिलाई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से भारत सरकार की ओर से अगले एक वर्ष तक अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इन विभिन्न आयोजनों के माध्यम से देश भर में वंदे मातरम् का पूर्ण गान होगा, जिससे देश की युवा पीढ़ी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को आत्मसात कर पाए।

आज जब हम भारत पर्व मना रहे हैं और सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं तो यह भी याद करते हैं कि कैसे सरदार साहब ने एक भारत का निर्माण कर वंदे मातरम् की भावना को ही मूर्त रूप दिया। यह गीत केवल अतीत का स्मरण मात्र नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक आह्वान भी है। वंदे मातरम् आज भी विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प को प्रेरणा दे रहा है। यह भारत के सभ्यतागत आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब इस भावना को आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत में परिवर्तित करना हमारी जिम्मेदारी है। वंदे मातरम् स्वतंत्रता का गीत है, अटूट संकल्प की भावना है और भारत के जागरण का प्रथम मंत्र है।

राष्ट्र के आत्मा से जन्मे शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वे सदैव जीवित रहते हैं, पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं। यह जयघोष युगों और पीढ़ियों में अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता रहेगा। समय आ गया है कि हम अपने समृद्ध इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं और अपनी परंपराओं को भारतीयता की दृष्टि से देखें।

वंदे मातरम्!

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)

response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

अंतरिक्ष में इसरो का बढ़ता दबदबा

रंजना मिश्रा

हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान एलवीएम3-एम5 ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। भारत का अब तक का सबसे भारी लगभग 4,410 किलोग्राम वजनी और अत्याधुनिक संचार सैटेलाइट सीएमएस-03 को उसकी निर्धारित भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में स्थापित करने की जिम्मेदारी इस 'बाहुबली' राकेट के कंधों पर थी। लगभग 43.5 मीटर ऊंचा और 640 टन से अधिक वजनी यह 'बाहुबली' राकेट भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक जीता-जागता नमूना है। यह अपने साथ 8,000 किलोग्राम तक का पेलोड निचली कक्षा में और 4,000 किलोग्राम से अधिक वजन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष की सबसे जटिल 'भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा' (जीटीओ) तक ले जाने की क्षमता रखता है। इस राकेट की असली ताकत इसका स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। यह एक ऐसी जटिल तकनीक है जिसमें शून्य से भी सैकड़ों डिग्री नीचे के तापमान पर तरल हाइड्रोजन और आक्सीजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एलवीएम3 की यह लगातार पांचवीं सफल उड़ान थी, जो चंद्रयान-3 जैसे ऐतिहासिक मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है।

सीएमएस-03 एक मल्टी-बैंड सैटेलाइट है, जो कई वर्षों तक भारत की संचार व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा

सीएमएस-03 एक मल्टी-बैंड सैटेलाइट है, जो कई वर्षों तक भारत की संचार व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। यह उपग्रह न केवल हमारे मुख्य भूभाग, बल्कि अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे दूर-दराज के द्वीपों तक हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद करेगा। इसका सबसे रणनीतिक लाभ हमारी नौसेना को मिलेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने और समुद्री गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए 'अंतरिक्ष में आंख और कान' की तरह काम करेगा।

एक समय था जब हमें अपने चार टन से अधिक वजनी सैटेलाइट को लांच करने के लिए फ्रांस या अन्य यूरोपीय देशों की मदद लेनी पड़ती थी। इसके लिए हमें उन्हें करोड़ों डालर की विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती थी। आज एलवीएम3 की सफलता ने इस निर्भरता को समाप्त कर दिया है। अब हम न केवल अपने सैटेलाइट खुद लांच कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देश भी अपने सैटेलाइट लांच करने के लिए किफायती और भरोसेमंद भारतीय राकेटों की ओर देख रहे हैं। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी सपना गगनयान मिशन यानी अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना इसी एलवीएम3 राकेट पर निर्भर है। इस राकेट की हर सफल उड़ान हमारे गगनयान मिशन के लिए विश्वास की गारंटी बनती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब हमारे 'गगनयात्री' इस राकेट पर सवार होंगे, तो उनकी सुरक्षा और सफलता शत-प्रतिशत पक्की होगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

डा. नवीन कुमार मिश्र

भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

आजकल

उभरते भारत के प्रति महाशक्तियों का रवैया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशिया की पांच दिवसीय यात्रा के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन बताता है कि अमेरिका चीन के साथ टकराव नहीं, बल्कि सुलह और सहयोग की स्थिति में है। इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने अपने सहयोगियों एवं विरोधियों दोनों को एकध्रुवीय विश्व का संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका ही वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और शांति को प्रभावित करता है। वहीं, अमेरिका, रूस और चीन के बीच हालिया आपसी रणनीतिक संबंधों से यह प्रतीत होता है कि भारत को अपनी वैश्विक रणनीति को भी परिवर्तनशील रखना होगा

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती निकटता से वैश्विक ध्रुवीकरण में परिवर्तन के प्रति भारत को सचेत रहना होगा। फाइल

अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति का लक्ष्य विश्व में जीवाश्म ईंधन बाजारों पर अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करना है। इसके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन उद्देश्य ठोस है। रूस की तेल से प्राप्त आय को नियंत्रित करने और चीन को रोकने की अमेरिका की मंशा के साथ ट्रंप जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से मुलाकात के बाद शी चिनफिंग के साथ 'एपेक' की बैठक में मिले, परंतु न तो शी चिनफिंग और न ही ट्रंप इस बैठक में किसी जीत का तार्किक रूप से उम्मीद कर सकते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध में शी चिनफिंग ने अपने रूसी गठबंधन का भू-राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया है। यूक्रेन में मास्को के युद्ध को समर्थन देकर और युद्ध प्रयासों में उत्तर कोरिया की उत्पादक और सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करके चीन रूस और पश्चिम दोनों को कमजोर करने में लगा हुआ है। पुतिन पूर्व-सोवियत संघ के पश्चिमी क्षेत्रों में रूसी नियंत्रण को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मध्य एशिया में तेल और संसाधन समृद्ध पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्रों में चीन की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव : दुर्लभ मृदा खनिजों के उत्पादन और शोधन में लंबे समय से चीन के प्रभुत्व ने अमेरिकी टैरिफ वार को विफल कर दिया। इसके अलावा, हरित प्रौद्योगिकी से लेकर दवाइयों तक चीन का विनिर्माण पर पश्चिमी देशों में निर्भरताएं हैं। परंतु मध्य-पूर्व में ईरान के प्रयास विफल होने से चीन के मुकाबले अमेरिका की स्थिति वहां मजबूत हुई है। अमेरिका द्वारा कनाडा, यूरोपीय संघ और भारत जैसे सहयोगियों और साझेदारों की आलोचना और निशाना बनाए जाने एवं यूएसएआइडी या संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग बंद करने जैसी डोनाल्ड ट्रंप की अव्यवस्थित नीतियों के कारण आज दुनिया को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

चिनफिंग और ट्रंप की निकटता : जब चीनी और अमेरिकी नेता बुसान में मिले तो उसके पहले यूरोप और जापान के रक्षा खर्च में लिया गया निर्णय ट्रंप के लिए एक ऐसी उपलब्धि के रूप में थी, जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं मिली है। बैठक का परिणाम रहा कि दुर्लभ खनिजों के मुद्दे पर चीन की ओर से बाधा का समाधान और अमेरिकी टैरिफ में कमी के रूप में सफलता हासिल हुई, परंतु बीजिंग और वाशिंगटन दोनों की आर्थिक नीतियां उनके व्यापक रणनीतिक हितों से निर्धारित होती हैं। कोई भी दूसरे के साथ युद्ध नहीं चाहता और दोनों ही अपनी प्रतिस्पर्धा जारी रखना चाहते हैं। टैरिफ कम करने से अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में तनाव कम जरूर होगा और वैश्विक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चिनफिंग व ट्रंप के बीच निकटता भारत के लिए चिंता का विषय है।

इसके साथ ही चीन के मित्र पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों का पुनर्निर्धारण और बीजिंग के साथ नई दिल्ली की अस्थायी शांति की पहल दक्षिण एशिया के रणनीतिक बदलाव की गतिशीलता को दर्शाता है, जो भारत-अमेरिकी संबंधों में तनाव के बीच हो रहा है। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए सजा दी जा रही है, जबकि चीन एक बड़ा खरीदार है और नाटो सहयोगी तुर्की और हंगरी भी बड़े आयातक हैं। भारत को लगता है कि अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने में मददगार है, लेकिन भारत को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

विश्व मंच पर भारत की भूमिका : महाशक्तियां उभरती हैं और उनका पतन भी होता है। आज दुनिया बदल रही है। ग्लोबल साउथ का उभार ट्रंप के एक ध्रुवीय विश्व के सपने को तोड़ रहा है। चीन की मजबूत होती रणनीतिक स्थिति के बावजूद ट्रंप ने अपनी चीनी नीति में बदलाव किया है। ट्रंप की नीति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के अमेरिका के दीर्घकालिक हित को भी प्रभावित करने वाला है, जिसने भारत सहित अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों को चिंतित कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच संतुलन में बदलाव व ट्रंप की अनिश्चितता ने क्षेत्र में सुरक्षा समीकरणों को भी स्पष्ट रूप से बदल दिया है। भारत ट्रंप के ऊंचे टैरिफ और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। अपने दोनों सबसे बड़े वैश्विक व्यापारिक साझेदारों के साथ घटते विश्वास के कारण विदेशी और आर्थिक संबंधों में उभरी जटिलताओं को नियंत्रित कर भारत को विश्व मंच पर अपनी एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

एशिया में भारत के बेहतर रिश्ते पश्चिमी देशों के साथ बेहतर तालमेल बैठाने में शक्ति प्रदान करने की स्थिति में हैं। जापान, भारत और आसियान देश मिलकर चीनी आर्थिक शक्ति को सीमित कर एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बना सकते हैं। भारत को पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत कर आर्थिक स्तंभों से जुड़ने की आवश्यकता है। एक असहज व्यापार युद्धविराम के बावजूद भारत को पूर्व की ओर अधिक आत्मविश्वास से देखना उचित कदम होगा। भारत के लिए एक अवसर है, क्योंकि अमेरिका केवल द्विपक्षीय सौदों में रुचि रखता है। इसके साथ ही हिंद-प्रशांत महासागर की रणनीति को भारत व आस्ट्रेलिया जैसे देशों के व्यापक निहितार्थों का मूल्यांकन करते हुए संशोधित नीति व दृष्टिकोण के माध्यम से भारत, आस्ट्रेलिया और जापान के साथ अपने सहयोग को मजबूत करके क्वाड के विकल्प के तौर पर 'ट्राई-एड' की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जो भारत के उभार को सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है।

वैश्विक आर्थिक संकट एवं भारत की संभावनाएं

राहुल पांडेय

शोधछात्र, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

विश्व अर्थव्यवस्था कोविड के बाद अनिश्चितता के दौर में जा चुकी है जिसमें चीन और अमेरिका के संघर्ष से निकली भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक संकट जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक संकट या फिर अवसर बन सकते हैं, लेकिन इस प्रतिद्वंद्विता ने पूरे विश्व को भविष्य को आर्थिक खतरों के संकेत देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से एआइ सेक्टर में जो कुछ हो रहा है, उसे वैश्विक वित्तीय इतिहास शायद 1929 के शेयर बाजार और 1998-99 के डाट-काम बबल जैसे संकट से पहले के समय से तुलना की जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण एआइ तकनीकी जैसे ओपनएआइ, एंथ्रोपिक एवं कुछ अन्य एआइ जैसी कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन लगभग 84 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। इस साल अकेले वेंचर कैपिटल निवेशकों ने एआइ सेक्टर में 13.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि गूगल, माइक्रोसाफ्ट, अमेजन और मेटा जैसी टेक कंपनियां 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक पूंजी एआइ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर चुकी हैं। निवेशकों की उम्मीदें इतनी ऊंची हैं कि इसके शेयर 40 गुना फारवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब वास्तविकता पर नजर डालें तो तस्वीर धुंधली दिखती है। ओपनएआइ की सालाना रेवेन्यू 1.09 लाख करोड़ रुपये है, जबकि घाटा 67 हजार करोड़ रुपये के आसपास है। यह सब उस दौर की याद दिलाता है जब 1999 में इंटरनेट कंपनियों के मूल्यांकन आकाश छू रहे थे। आज वही कहानी डाटा सेंटर्स के रूप में दोहराई जा रही है। विश्व मुद्रा कोष तक चेतावनी दे चुका है कि एआइ निवेश इकोनमिक बबल का रूप ले रहा है, जो डाट-काम क्रैश जैसी तबाही ला सकता है।

भारत के लिए यह वैश्विक उथल-पुथल केवल बाहरी संकट नहीं, बल्कि उसकी विकास के रास्ते की परीक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 30-35 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था, 15 से 18 हजार रुपये की प्रति व्यक्ति आय और शून्य गरीबी का है। इसे हासिल करने के लिए भारत को अगले 23 वर्षों तक आठ से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर चाहिए जो इतिहास में किसी बड़े देश ने स्थायी रूप से हासिल नहीं की, चीन ने भी नहीं। भारत में 2025 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा और स्थिर उपभोग मांग जो लगभग भारत की जीडीपी का लगभग 61 प्रतिशत है, बड़ी विशेषता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यह केवल आंकड़ों की कहानी नहीं यह संरचनात्मक असंतुलन की कहानी है। जब घरेलू संपत्ति का बड़ा हिस्सा सोने में फंसा हो और विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 16-17 प्रतिशत हो (सरकार का लक्ष्य 25 प्रतिशत), तब विकास को टिकाऊ बनाना कठिन है।

भारत की आयातित मुद्रास्फीति पहले से ही बढ़ रही है। जून 2024 में 1.3 प्रतिशत से फरवरी 2025 में 31.1 प्रतिशत तक। रिजर्व बैंक के लिए यह असंभव विकल्प की स्थिति है या तो ब्याज दरें बढ़ाकर रुपये की रक्षा करें (जिससे विकास ठंडा पड़ेगा) या गिरती मुद्रा को स्वीकार करें। और अगर भारत अगले कुछ साल चार प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की जगह धीमी वृद्धि करता है, तो 2047 में अर्थव्यवस्था लक्ष्य से लगभग 10 ट्रिलियन डालर तक कम रहने की आशंका है। इतिहास कहता है कि बबल हमेशा फूटते हैं। सवाल यह नहीं कि कब, बल्कि यह कि कौन तैयार है। भारत के लिए यह चुनौती है कि जब बाकी दुनिया अस्थिरता में उलझी है, क्या वह अपने रास्ते पर अडिग रह सकता है? अगर हां, तो विकसित भारत 2047 केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था में भारत की सशक्त उपस्थिति का प्रतीक बन सकता है।

मंथन

डिजिटल दौर की नई समस्याएं

डा. मुकुल श्रीवास्तव

प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दिया है। परंतु इसने कुछ नई समस्याएं भी पैदा की हैं, जिनके समाधान के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए

डिजिटल संचार जहां एक ओर संवाद को तात्कालिक और सुलभ बना रहा है, वहीं दूसरी ओर यह हमारी निजी और कामकाजी जिंदगी की सीमाओं को धुंधला कर रहा है। मसलन वाट्सअप, मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग एप वैश्विक संचार का पर्याय बन गया है। स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में लगभग 2.7 अरब और भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग इस एप का इस्तेमाल करते हैं। यह अब मात्र व्यक्तिगत चैट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। हालांकि हमें इस सुविधा की एक कीमत चुकानी पड़ रही है। हमेशा आन रहने की संस्कृति ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां काम के घंटे अनिश्चित हो गए हैं। साल 2023 में आई स्लैक की 'स्टेट आफ वर्क रिपोर्ट' के अनुसार, दुनियाभर में 53 प्रतिशत डेस्क वर्कर्स काम के बाद भेजे गए संदेशों का जवाब देने का दबाव महसूस करते हैं। 'सैंसेस वाइड' द्वारा किए एक सर्वे के मुताबिक, 88 प्रतिशत कर्मचारियों से नियमित रूप से काम के घंटों के बाद भी उनसे काम से संबंधित संपर्क किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट भी इस बात पर प्रकाश डालती है कि डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले कर्मचारी न केवल अधिक घंटे काम करते हैं, बल्कि अपने काम और जीवन के बीच संघर्ष का अनुभव करते हैं। वाट्सअप 'डिजिटल प्रेजेंटिज्म' नाम की इस नई घटना को जन्म देता है जहां कर्मचारी दफ्तर में न होने पर भी आनलाइन उपलब्ध रहने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। यह ईमेल प्रकृति के ठीक विपरीत है, जहां कर्मचारी को सोचने और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। वाट्सअप का 'ब्लू टिक' और 'लास्ट सीन' फीचर इस दबाव को और बढ़ा देता है, जिससे एक अलिखित अपेक्षा पैदा होती है कि संदेश देख लिया गया है तो उसका तुरंत जवाब भी दिया जाना चाहिए।

एक औपचारिक ईमेल के माध्यम से किए गए अतिरिक्त काम के अनुरोध करना आसान होता है, लेकिन वही अनुरोध अगर वाट्सअप पर एक अनौपचारिक, मैत्रीपूर्ण संदेश के रूप में आता है तो उसे मना करना असभ्य लग सकता है। वस्तुतः हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है, लेकिन वाट्सअप हमें लगातार कोड स्विचिंग के लिए मजबूर करता है, एक पल में आफिस का कोई महत्वपूर्ण काम, वहीं दूसरे पल फैमिली ग्रुप पर व्यक्तिगत चैट। निरंतर मल्टीटास्किंग हमारी कार्यशील मेमोरी कमजोर करती है जो बर्नआउट की ओर ले जाती है।

वैसे तो यह घटना वैश्विक है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक, आर्थिक कारक इसे कहीं अधिक गंभीर चुनौती बना देते हैं। इस प्रवृत्ति का असर निजी रिश्तों पर भी पड़ा है। परिवार या दोस्तों के साथ बिताया जाने वाला समय अब लगातार कामकाज संबंधी संदेशों से बाधित होता है। परिणामस्वरूप रिश्तों में यह शिकायत आम हो चली है कि लोग हमेशा फोन पर व्यस्त रहते हैं या रात देर तक भी आफिस का काम निपटाते रहते हैं। मनोविज्ञानी इस घटना को टेक्नोफिरेंस कहते हैं, जिसका अर्थ है तकनीक द्वारा व्यक्तिगत संबंधों में पैदा की जाने वाली बाधा। इस तरह डिजिटल संचार ने काम और निजी जिंदगी की सीमाएं धुंधली की हैं, और निजी संबंधों को भी प्रभावित किया है।

लघु, मध्यम उद्यमों और असंगठित क्षेत्र की समस्या : भारत में लाखों लघु, मध्यम उद्यमों और असंगठित क्षेत्र के लिए वाट्सअप न केवल एक मैसेजिंग एप है, बल्कि उनका पूरा बिजनेस सिस्टम है। यह उनका सीआरएम, आर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग टूल और ग्राहक सहायता केंद्र है। यह निर्भरता इतनी गहरी है कि इससे डिस्कनेक्ट होने का मतलब अक्सर व्यवसाय से डिस्कनेक्ट होना है। हालांकि इस कानून पर कई बार बहस तो हुई है, परंतु इसे यहां लागू करना एक जटिल चुनौती बनी हुई है।

भारत जैसे देश में जहां सेवा आधारित अर्थव्यवस्था और नौकरी असुरक्षा जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, वहां पर इस तरह के कानून को लागू करना भी बहुत जटिल है। हालांकि अब समय आ गया है जब लोगों और कंपनियों को इसके समाधान की दिशा में सक्रियता से काम करना होगा। कंपनियों को एक विस्तृत कम्युनिकेशन चार्टर या नीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कि किस संचार के लिए कौन सा प्लेटफार्म उपयोग किया जाए। साथ ही अपेक्षित प्रतिक्रिया का समय, टाइम को डिस्कनेक्ट इसकी भी नीतियां बनाई जानी आवश्यक हैं।

प्रतीकात्मक

व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों को भी डिजिटल वेलनेस की आवश्यकता है जिसमें काम के बाद वर्क ग्रुप्स को म्यूट करना, संचार के लिए आधिकारिक चैनल का ही उपयोग करना तथा अपनी सीमाओं को विनम्रतापूर्वक अपनी टीम और कंपनी तक पहुंचाना। क्योंकि यदि हम अभी काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने में विफल होते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत रिश्तों को हानि पहुंचा रहे हैं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं जो हमेशा कनेक्टेड रहने के बावजूद असली जिंदगी से कट जाएगी।

****

पांच क्षेत्र बनाएंगे भारत को आत्मनिर्भर : सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा- आर्थिक, सामाजिक, टेक्नोलाजी, रणनीतिक और ऊर्जा सेक्टर में मजबूती जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पांच सेक्टरों में मजबूत बुद्धि की जरूरत है। इनमें आर्थिक, सामाजिक, टेक्नोलाजी, रणनीतिक व ऊर्जा सेक्टर शामिल हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के कान्क्लेव में गुरुवार को वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना नहीं है। इसका मतलब है घरेलू स्तर पर ही अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना और वैश्विक सप्लाई चेन में प्रमुख हिस्सेदार बनना। आत्मनिर्भर का मतलब है कि भारत अपने लिए और दुनिया के लिए खुद डिजाइन करे, उत्पादन करे और इनोवेट करे। उद्यमिता और आत्मविश्वास से भरी हुई अर्थव्यवस्था हो।

सीतारमण ने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी कही जाएगी जब राष्ट्र में अपनी समृद्धि की कहानी लिखने की क्षमता हो। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए किसी देश के माडल की नकल नहीं कर सकते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय समावेश और वित्तीय मजबूती भी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से काम शुरू हो चुका है। पिछले 11 सालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में पांच गुने की बढ़ोतरी हुई है। 56 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं। मुद्रा लोन के 52 करोड़ खाते हो चुके हैं। सीतारमण ने कहा कि सामाजिक आत्मनिर्भरता मतलब है समाज और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना। जब देश के सभी नागरिक अपनी मर्जी से राष्ट्र के विकास में भागीदारी करने में सक्षम हो जाए।

- आत्मनिर्भर होने का मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना नहीं
- आत्मनिर्भरता के लिए अन्य देश के माडल की नकल नहीं कर सकते

मुंबई में गुरुवार को एसबीआइ बैंकिंग एंड इकोनामिक्स कान्क्लेव 2025 को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण • पीटीआइ

देश को बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की जरूरत: वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की जरूरत है। विश्वस्तरीय बैंकों के निर्माण के लिए आरबीआइ से चर्चा चल रही है। वर्ष 2017 में एसबीआइ में कई बैंकों का विलय किया गया था। उसके बावजूद वैश्विक बैंकों में एसबीआइ 43वें नंबर पर है। सरकार चाहती है कि दुनिया के शीर्ष 10 बैंकों में भारतीय बैंक का स्थान हो। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए मैन्यूफैक्चरिंग और औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन की जरूरत है और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। बैंकों को उद्योग जगत खासकर एमएसएमई को सस्ते और समय पर लोन देना चाहिए। आसानी से कर्ज की सुविधा से ही उद्यमिता और इनोवेशन का लगातार विकास संभव है। कोरोना के बाद बैंकों के विलय या उनमें सरकारी हिस्सेदारी को कम करने के मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सका है।

स्थानीय भाषा जानने वाले कर्मचारियों की भर्ती करें बैंक

मुंबई प्रेट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगर बैंकों को ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाना है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शाखा में काम करने वाले कर्मचारी को स्थानीय भाषा आती हो। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों से जुड़ाव कम होने के चलते क्रेडिट सूचना कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई है और वह डेटा अपडेट करने में लंबा समय लेती हैं, जिसके चलते बैंक ग्राहकों को ऋण देने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने एचआर पालिसी में बदलाव की भी वकालत की ताकि यह सुनिश्चित हो सके स्थानीय भाषा बोलने वाले लोगों की ही बैंकों में भर्ती हो। इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिटेल इन्वेस्टर को बाक्ड एवं विकल्प (एफएंडओ) में काम करने से नहीं रोक सकती है। हालांकि, सरकार इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता जरूर पैदा करेगी। यह बयान सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे द्वारा निफ्टी और सेंसेक्स में साप्ताहिक डेरिवेटिव अनुबंधों को बंद करने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशकों की जिम्मेदारी है कि वे इसमें शामिल जोखिमों को समझें।

Dainik Jagaran Page No-10

न्यूजीलैंड की मदद से छोटी-छोटी प्रोसेसिंग यूनिट का बिछ सकता है जाल

जयशंकर रंजन • जागरण

रोटोरुआ (न्यूजीलैंड) : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि न्यूजीलैंड की प्रौद्योगिकी की मदद से भारत में छोटी-छोटी दुग्ध प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की जाए। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बातचीत चल रही है और यह मुद्दा दोनों देशों के बीच एक अहम विमर्श का केंद्र है।

दो दिनों की लगातार वार्ता के बाद यहां गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि वार्ता काफी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टाड मैकाले ने बताया कि वह ट्रेड वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते फिर से भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। मैकाले पिछले दो वर्षों में पांच बार भारत का दौरा कर चुके हैं, जो बताता है कि न्यूजीलैंड भारत के साथ कारोबारी समझौते को लेकर कितना संजीदा है।

- वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है व्यापार वार्ता
- आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएई के साथ कारोबारी समझौतों को अंतिम रूप दे चुका है भारत

न्यूजीलैंड में अपने समकक्ष टाड मैकाले के साथ व्यापार वार्ता करते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल • @पीयूष गोयल

वाणिज्य मंत्री गोयल की अगुआई में भारत ने आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएई के साथ कारोबारी समझौते को अंतिम रूप दिया है जबकि अभी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड समेत कई देशों के साथ एफटीए की बातचीत अंतिम चरण में है। गोयल ने न्यूजीलैंड के साथ चल रही वार्ता के बारे में बताया कि, हालांकि, इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 20 अरब डालर की है। चीन दक्षिण अमेरिका को सालाना 500 अरब डालर से अधिक का निर्यात करता है। इसे ध्यान में रखते हुए ही वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय अब पेरू व चिली जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ क्रॉपेहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के साथ व्यापार समझौते को लेकर तीन राउंड की बातचीत हाल ही में पूरी हुई है। वार्ता सफल तरीके से आगे बढ़ रही है और अगले साल पूरी उम्मीद है कि जल्द ही एफटीए की घोषणा हो जाएगी। चूंकि इस समझौते का असर दोनों देशों की स्थिति पर आने वाले कई दशकों तक होगा, इसलिए हम काफी संभल-संभल कर कदम उठा रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से इसको लेकर पूरी प्रतिबद्धता है। यह दोनों देशों के बीच सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि रणनीतिक व एक दूसरे की आम जनता के बीच भी प्रगाढ़ संबंधों की नई शुरुआत होगी।

पेरू-चिली के जरिये दक्षिण अमेरिका में व्यापार विस्तार की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अमेरिका-यूरोप में भले ही भारत का वस्तु निर्यात लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देशों में अब भी भारत की निर्यात हिस्सेदारी अत्यंत कम है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 440 अरब डालर का निर्यात किया था और इनमें सिर्फ 20 अरब डालर का निर्यात दक्षिण अमेरिका में किया गया।

दक्षिण अमेरिका में 30 से अधिक देश हैं और सभी देश मिलाकर सालाना 1.4 ट्रिलियन डालर का आयात करते हैं। आरंभ में इन देशों के साथ व्यापार समझौता हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, पेरू और चिली जैसे देशों में दुर्लभ खनिज पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन देशों के साथ समझौता होने पर दुर्लभ खनिज पदार्थ हासिल करने में आसानी होगी। जानकारों का कहना है कि पेरू की अर्थव्यवस्था का आकार भले ही मात्र 300 अरब डालर का है, लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय सालाना 7,000 डालर है और लोगों की खरीदारी क्षमता काफी अधिक है।

न्यूजीलैंड के कारोबार मंत्री टाड मैकाले ने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच दो अरब डालर से भी कम का कारोबार होता है, जो इनकी क्षमताओं को देखते हुए काफी कम है। हालांकि, मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय कारोबार जल्द ही बढ़कर 20 अरब डालर का हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देश व्यापार समझौता करने के विषय में अभी किसी कारोबारी लक्ष्य को लेकर विचार-विमर्श नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने चीन के साथ एफटीए का उदाहरण दिया। आज चीन और न्यूजीलैंड के बीच 40 अरब डालर का कारोबार होता है।

Dainik Jagaran Page No-10

सैन्य शासित देश बनने की ओर बढ़ा पाक, मुनीर को असीमित अधिकार देने की तैयारी

- पाकिस्तान के संविधान में 27वें संशोधन की तैयारी, अनुच्छेद 243 में सुधार से फील्ड मार्शल पद बन जाएगा संवैधानिक
- प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह पांच साल का होगा कार्यकाल, सेना प्रमुख नियुक्त करने का मिलेगा अधिकार
- लागू होगा हाइब्रिड शासन, सरकार को फैसला अमल में लाने के लिए फील्ड मार्शल से लेनी होगी सहमति
- फील्ड मार्शल को अदालत में नहीं दी जा सकेगी चुनौती, अमेरिका और चीन से जुड़ी परियोजनाओं में होगा दखल

नई दिल्ली, आइएएनएस: पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को असीमित अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शुक्रवार को ऊपरी सदन, सीनेट में 27वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। तमाम बदलावों के साथ-साथ अनुच्छेद 243 में भी संशोधन होगा। इसके बाद मुनीर सर्वेसर्वा बन जाएंगे। सरकार को भी कोई फैसला लागू कराने से पहले मुनीर की सहमति लेनी होगी। वह सेना प्रमुख और अन्य कमांडरों की तैनाती कर सकेंगे। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह पांच साल का होगा। साथ ही उनको देश की किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। सीनेट से पास होने के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल असेंबली में रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आसिम मुनीर का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है, जबकि वह 2028 तक पद पर बने रहना चाहते थे। मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया था, लेकिन ये केवल औपचारिक पद था।

आसिम मुनीर। फाइल

संविधान संशोधन नहीं, ये मुनीर संशोधन

राजनीतिक मोर्चे पर लिए गए अपने कई फैसलों के कारण आसिम मुनीर पिछले कुछ समय से अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस संशोधन के माध्यम से मुनीर बेखौफ फैसले ले सकेंगे। उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि निश्चित रूप से यह संशोधन मुनीर के लिए ही किया जा रहा है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान बाकी दुनिया के लिए एक लोकतंत्र बना रहे, जबकि अंदरखाने वह एक सैन्य शासन में तब्दील हो जाएगा। सेना प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार मुनीर को अपनी पसंद के लोगों को नियुक्त करने का अवसर देगा। सशस्त्र बलों और आइएसआइ पर नियंत्रण पूरे देश पर नियंत्रण रखने के बराबर है।

विशेषज्ञों के मुताबिक : सैन्य तख्तापलट का खेल खत्म हो जाएगा

विशेषज्ञों के मुताबिक संशोधन पारित होने के बाद पाकिस्तान में हाइब्रिड शासन लागू हो जाएगा। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार फील्ड मार्शल के हाथों की महज कठपुतली होगी। इसके अलावा, संसाधनों की खनन परियोजनाओं और बुनियादी निवेशों को भी प्रबंधित करने का अधिकार सेना के पास होगा। सेना का मानना है कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं क्योंकि इसमें अमेरिका और चीन की कंपनियां शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर ये संशोधन पारित हुआ तो सरकार फील्ड मार्शल के अधीन हो जाएगी। इससे लोगों के मतदान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि मुनीर अगले पांच साल तक सत्ता में मनमानी कर सकेंगे। मुनीर ने इतनी चतुराई से संशोधन कार्ड खेला है कि इससे सैन्य तख्तापलट की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार को फैसले लागू कराने से पहले मुनीर की सहमति लेनी होगी।

27वें संशोधन के बाद फील्ड मार्शल का पद संवैधानिक रूप से स्थापित हो जाएगा। इसके बाद मुनीर को न्यायिक और राजनीतिक, दोनों तरह की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। संविधान संशोधन के जरिये सेना अधिनियम, 1952 में भी संशोधन किए जाएंगे। इससे ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा। इस संशोधन से फील्ड मार्शल के अधीन उप-सेना प्रमुख का पद भी सृजित होगा। इसके अलावा, सेना प्रमुखों का कार्यकाल भी पांच वर्ष निर्धारित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान की सत्ता में सेना का प्रभुत्व रहा है। उसके कई सेना प्रमुखों ने तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा किया।

Dainik Jagaran Page No-11

दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे मस्क! 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा होगी दौलत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- टेस्ला के एक ट्रिलियन डालर के बोनस प्लान से मस्क की संपत्ति में हो सकती है कई गुना बढ़ोतरी
- एक ट्रिलियन डालर शेयर और स्टाक के रूप में मिलेंगे, जिससे टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी दोगुनी होगी
- खरबपति बनने के लिए टेस्ला को 8.5 ट्रिलियन डालर कीमत वाली कंपनी बनाना होगा
- 500 अरब डालर की संपत्ति के मालिक हैं एलन मस्क

एलन मस्क। फाइल

दुनिया की दिग्गज कार कंपनी 'टेस्ला' और ट्विटर के मालिक एलन मस्क जल्द ही एक ट्रिलियन डालर (यानी 84 लाख करोड़ रुपये) के मालिक बन सकते हैं। टेस्ला के नए एक ट्रिलियन डालर के बोनस प्लान से उनकी संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। ये रकम 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। मस्क को अगले 10 वर्षों में एक ट्रिलियन डालर शेयर व स्टाक के रूप में मिल सकता है। टेस्ला के सीईओ के तौर पर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी भी मौजूदा 13 प्रतिशत से बढ़कर दो गुना हो जाएगी। ज्ञात हो, वर्तमान में मस्क के पास 500 अरब डालर की संपत्ति है।

क्या है टेस्ला का बोनस प्लान: टेस्ला के नए बोनस प्लान की वजह से कंपनी की कीमत भी 8.5 ट्रिलियन डालर हो सकती है। टेस्ला के नए बोनस और शेयर पैकेज पर कंपनी शेयरधारकों की बैठक में सहमति बन सकती है। टेस्ला बोर्ड ने ऐसा प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत यदि कंपनी 8.5 ट्रिलियन डालर के बाजार मूल्य तक पहुंचती है, तो मस्क को एक ट्रिलियन डालर का स्टाक पैकेज मिलेगा। वर्तमान मूल्य की तुलना में ये आठ गुना ज्यादा है। मस्क का लक्ष्य है कि टेस्ला अगले 10 सालों तक 400 अरब डालर की कमाई करे। ज्ञात हो, फोर्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों की संपत्ति 1.7 ट्रिलियन डालर है। 2024 में आक्सफैम (वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए गठित ब्रिटिश संस्था) ने अनुमान जताया था कि दुनिया को पहला खरबपति इसी दशक में मिल जाएगा। संस्था के दावे के 12 महीने में ही ये सच लगने लगा है। संस्था के दावे के मुताबिक दुनिया को जल्द पांच नए खरबपति मिल सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में अरबपतियों की संपत्ति दो ट्रिलियन डालर बढ़ी, यानी रईसों ने रोज छह अरब डालर से ज्यादा कमाए और हर हफ्ते चार नए अरबपति सूची में जुड़ रहे हैं।

****

Dainik Jagaran Page No-11

भीड़ प्रबंधन की अनदेखी से बढ़ते हादसे

आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मची भगदौड़ से कई लोगों की मौत कोई पहला हादसा नहीं है। सवाल यह है कि बार-बार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं और हम इससे सबक क्यों नहीं लेते? ऐसी दुर्घटनाओं का सिलसिला बरसों से जारी है।

योगेंद्र माथुर

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बीते दिनों भगदड़ में दस श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। जैसा कि अब तक होता आया है, सभी बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों ने दुर्घटना पर शोक संवेदना जताते हुए इस घटना की जांच कराने की मांग की। उधर, स्थानीय पुलिस और प्रशासन दुर्घटना की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते रहे। प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन द्वारा दर्शन व्यवस्था की पूर्व सूचना न देने से सुरक्षा व्यवस्था न हो पाने की बात कही। मुख्य रूप से दर्शनार्थियों की अनुमान से अधिक भीड़ जुटने, मंदिर का प्रवेश-निकास द्वार एक ही होने और व्यवस्था के लिए लगे अवरोधक गिरने से भगदड़ मचने की बात कही गई। वहीं प्रवेश और निकास द्वार संकरा बताया गया। बहरहाल, यह पहला अवसर नहीं है जब किसी धार्मिक स्थल पर भगदड़ मची हो और श्रद्धालुओं की जान गई हो। ऐसी दुर्घटनाओं का सिलसिला बरसों से जारी है।

हाल के वर्षों में कई दुर्घटनाएं हुईं जिनमें सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसी वर्ष उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में हुए आयोजनों में ऐसी लगभग एक दर्जन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अकेले आंध्रप्रदेश में ही धार्मिक स्थलों पर भगदड़ की इस वर्ष यह तीसरी दुर्घटना है। मगर इन दुर्घटनाओं से कोई सबक लिया गया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता।

आए दिन पर्व-त्योहारों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसी के साथ कई छोटे-बड़े धार्मिक आयोजन यथा मेले, कथा-सत्संग और प्रवचन कहीं न कहीं होते रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। धार्मिक आयोजनों से इतर कई सामाजिक, सांस्कृतिक और संगीत आयोजनों के साथ राजनीतिक सभाएं-रैलियां भी होती हैं, जिनमें खासी भीड़ जुटती है। इन अवसरों पर भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन एवं सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है। आयोजन सकुशलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो ठीक, नहीं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर लीपापोती करने में स्थानीय प्रशासन की पूरी मशीनरी जुट जाती है। राजनीतिक पार्टियां दुर्घटना पर शोक व्यक्त कर और सरकारें जांच कमेटी या आयोग का गठन कर अथवा मुआवजे का मरहम लगा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं। बाद में समय के साथ जख्म भरते जाते हैं। दुर्घटना को लगभग भुला दिया जाता है, जब तक कि कोई नई दुर्घटना न हो जाए। इन दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लेता।

प्रायः देखा जाता है कि समुचित सुरक्षा-व्यवस्था न होने अथवा कुप्रबंधन के कारण भगदड़ मचती है। कई बार आयोजनों से जुड़े प्रबंधन और प्रशासन की घोर लापरवाही या अनदेखी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। अधिकांश बड़े आयोजनों या राजनीतिक रैलियों के दौरान यह देखने में आता है कि आयोजकों का पूरा ध्यान अपनी शक्ति, सामर्थ्य अथवा लोकप्रियता के प्रदर्शन पर रहता है। व्यवस्था और जन सुरक्षा को हाशिये पर डाल दिया जाता है। दुर्घटना से बचने के कोई प्रबंध नहीं किए जाते। ऐसे अवसरों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए नियम और

कानून के तहत आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। किसी भी आयोजन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए, जब आयोजक सुरक्षा-व्यवस्था की संतोषजनक कार्ययोजना प्रस्तुत करें। आयोजकों के प्रबंधन कौशल का भी आकलन किया जाना चाहिए।

> भारत में भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर ठोस नीति या कार्ययोजना का अभाव रहा है। यही कारण है कि अत्यधिक भीड़ जब-तब भगदड़ या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की वजह बनती है। अनुमान से अधिक आई भीड़ को प्रायः दुर्घटना का कारण बताया जाता है, लेकिन वर्तमान तकनीकी दौर में संभावित भीड़ का अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की सहायता से भीड़ पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने पर पर उपग्रहों से जन सघनता की जांच करने वाले 'ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर' को जोड़ कर और निगरानी कर ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

वैसे भारत में भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर ठोस नीति या कार्ययोजना का सदैव अभाव रहा है। यही कारण है कि अत्यधिक भीड़ जब-तब भगदड़ या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की वजह बनती है। अनुमान से अधिक आई भीड़ को प्रायः दुर्घटना का कारण बताया जाता है, लेकिन वर्तमान तकनीकी दौर में संभावित भीड़ का अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की सहायता से भीड़ पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने पर पर उपग्रहों से जन सघनता की जांच करने वाले 'ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर' को जोड़ कर और निगरानी कर ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। हर भीड़ अव्यवस्था या भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं में बदल सकती है। लिहाजा यह मान कर ही किसी भी भीड़ वाले आयोजन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था तय की जानी चाहिए। किसी भी आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ बढ़ने की संभावना पर उसके सीधे प्रसारण का कई स्थानों पर प्रबंध कर भीड़ को एक ही जगह जमा होने से रोका जा सकता है। यह सबसे सुरक्षित तरीका है।

पर्व-त्योहारों पर आम तौर पर दर्शन-पूजा के लिए भीड़ उमड़ती है। इन अवसरों पर कथा-सत्संग और प्रवचनों के छोटे-बड़े आयोजन भी होते रहते हैं। इस तरह के अवसरों पर श्रद्धालुओं में पहले दर्शन और प्रसाद पाने की होड़ अथवा आगे बढ़ने या बैठने की आपाधापी सामान्य बात होती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा-व्यवस्था की पहले से कार्ययोजना तैयार की जाना चाहिए और आयोजन स्थल पर पर्याप्त अवरोधक लगाने के साथ पुलिस बल के अलावा मंदिर प्रबंधन या आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा-व्यवस्था में तैनात किया जाना चाहिए। फिसलन भरी जगह या संकरे मार्ग भी दुर्घटना की वजह बनते हैं। प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि आयोजन स्थलों पर विद्युत व्यवस्था के तार बेतरतीब तरीके से लगे होते हैं या लटके होते हैं। ऐसे में वहां करंट लगने या फैलने का खतरा बन जाता है। ऐसे में भगदड़ की स्थिति बन जाती है और श्रद्धालु अपनी जान गंवा देते हैं। तेज हवा या बारिश के समय ऐसी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं।

सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा करते समय ऐसी आशंकाओं को रोकने की तरफ भी विशेष ध्यान होना चाहिए। अत्यधिक भीड़ की स्थिति में आयोजन स्थलों पर प्रवेश व निर्गम द्वार की व्यवस्था अनिवार्य हो। वहां पेयजल, चिकित्सा व जनसुविधा परिसर की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इन स्थानों पर आग की स्थिति से निपटने के लिए दमकल सेवाओं के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण होती है। ऐसे में कोई दुर्घटना होने पर बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। कई बार छोटी-मोटी घटनाएं भी अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं के फैलने से बड़ी दुर्घटना में बदल जाती हैं। कहीं आग लगने या करंट फैलने की अफवाहों के कारण भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। अधिक भीड़ जुटने वाले अवसरों और इन स्थलों पर नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र या नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, ताकि समय रहते लोगों को सचेत किया जा सके।

अफवाहों पर नियंत्रण कर बड़ी दुर्घटनाओं रोका जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी स्थल या आयोजन में जुटने वाली भीड़ की संख्या का पूर्वानुमान या आकलन सदैव सही साबित हो। भीड़ अनुमान से अधिक भी हो सकती है। मगर समझे जरूरी है लोगों में अनुशासन, सावधानी और सचेतनता। ऐसा हो, तो भगदड़ पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। मगर आखिर में यही सवाल है कि हम इन हादसों से कब सबक लेंगे?

Jansatta Page No-6

Business Standard Page No-1

Jansatta Page No-10

संभावनाओं की राह

राजेंद्र जोशी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप देश के सामने नई दृष्टि के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया है। यह दावा किया गया कि यह इक्कीसवीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इस पर कोई विवाद भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार 1986 में बनी नीति को केवल 1992 में संशोधित किया गया था। लगभग तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद बनी यह नीति भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के समसामयिक संदर्भों को ध्यान में रखकर रची गई है। पर सवाल यह है कि पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी नई शिक्षा नीति देश भर में प्रभावी और समान रूप से लागू क्यों नहीं हो पाई है? आज भी विभिन्न राज्य नई शिक्षा नीति के विविध घटकों को अपने-अपने ढंग से अपनाने में व्यस्त हैं, जिससे शिक्षा के राष्ट्रीय मानक और रूप-रेखा असंतुलित हो रही है। नीति का उद्देश्य तो देश में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समावेशी शिक्षा व्यवस्था को साकार करना था, लेकिन इसके व्यावहारिक स्वरूप में अनेक अड़चनें हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधारभूत मंत्र है- समग्र शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नवाचार को एक साथ जोड़ने का प्रभावी प्रयास होना चाहिए। सरकार की मंशा रही है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और चिंतन की सनातन परंपरा केवल ग्रंथों तक सीमित न रहकर नई पीढ़ी की शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बने। भारत की आत्मा में ज्ञान, मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टि का संगम सदा से रहा है और यह बरसों से हमारे देश का प्राण रहा है। अब शिक्षा के माध्यम से उसी आत्मा को आधुनिक युग के संदर्भों में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता समझकर शिक्षा नीति अमल में लाने का प्रयास है। मगर यह नीति केवल विषयों और पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह शिक्षा की सोच, दृष्टि और उद्देश्य को नव-परिभाषित करने का प्रयास होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को सशक्त बनाए। नीति में 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई है, जो बच्चों के मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के चरणों को ध्यान में रखती है।

यह व्यवस्था पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक निरंतर और समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। सबसे बड़ी चुनौती राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय की है। शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विभिन्न राज्यों में नीति को लागू करने की गति और इच्छाशक्ति में भिन्नता है, जिससे नीति का राष्ट्रीय स्वरूप कमजोर पड़ता दिख रहा है।

शिक्षक किसी भी शैक्षणिक सुधार की धुरी होते हैं, पर अधिकांश शिक्षक नई नीति के उद्देश्यों और मूल्य धाराओं से परिचित नहीं हैं। इसके लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षणिक संसाधनों और मूल्य-आधारित शिक्षण पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता है। तीसरी चुनौती है बुनियादी ढांचे और संसाधन की। अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, तकनीकी उपकरण और शोध संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता का समन्वय नीति की एक विशेषता भर नहीं, लेकिन धरातल पर होना चाहिए।

शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना और समाज कल्याण के मार्ग पर चलना रहा है। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है। मगर इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन-केंद्र स्थापित किए जाएं, पारंपरिक विद्वानों को नई तकनीक और शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा विद्यार्थियों को इन विषयों में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाएं। नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई है। यह विचार भारतीय भाषाई विविधता को सम्मान देता है और बच्चों की सोच तथा सीखने की क्षमता को मजबूत करता है। मगर इस दिशा में भी व्यावहारिक जटिलताएं हैं। इसके साथ एक सामान्य भाषा-संपर्क भी आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, शोध और संवाद की एकरूपता बनी रहे। यह संतुलन ही भारत की बहुभाषिकता को सशक्त बनाएगा।

दुनिया मेरे आगे

> शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना और समाज कल्याण के मार्ग पर चलना भी है। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है। मगर इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन-केंद्र स्थापित किए जाएं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम सुधार नहीं, बल्कि एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज का निर्माण है। प्रत्येक राज्य और संस्था को निश्चित समय सीमा में नीति के बिंदुओं को लागू करने का दायित्व सौंपा जाए और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा हो, तभी नीति का लक्ष्य साकार हो सकता है। जब शिक्षा केवल परीक्षा और डिग्री केंद्रित न रहकर नवोन्मेष और विचारशीलता की दिशा में उन्मुख होगी, तभी भारत एक सशक्त ज्ञान राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। यह नीति उस भारत की कल्पना करती है जो ज्ञान, मूल्य और नवाचार का प्रतीक बने। जब गुरु, विद्यार्थी और समाज तीनों इस दृष्टि को अपनाएंगे, तभी भारत उस ज्ञानभूमि के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जिसकी प्रेरणा से पूरी मानवता मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।

Jansatta Page No-6

डेढ़ सौ साल से हमें जगाता वंदे मातरम्

योगी आदित्यनाथ | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर आत्म-निरीक्षण का क्षण भी है। क्या हम उस भाव को जी पा रहे हैं, जिसके लिए असंख्य देशभक्तों ने प्राणों की आहुति दी?

वंदे मातरम्... यह केवल उच्चरित शब्द नहीं है, यह भारतीय आत्मा का वह शाश्वत निनाद है, जो डेढ़ शताब्दी से अनवरत गुंजित हो रहा है। यह मात्र गीत नहीं, राष्ट्र-जागरण का वह दिव्य महामंत्र है, जिसने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारत को आत्मबोध का प्रकाश दिया, निराशा के घोर तमस में अस्मिता की ज्योति प्रज्वलित की, संघर्ष को संबल और स्वाधीनता को स्वरूप प्रदान किया।

इस गीत में न तो सत्ता का मोह है, न किसी जाति, संप्रदाय या प्रांत का आग्रह। यह गीत संपूर्ण भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वह चेतना, जो हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म से निर्मित हुई है। इस गीत ने हमें यह सिखाया कि राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील, मातृस्वरूपा सत्ता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण ही हमारी असली पहचान है। यह गीत भारतीय जीवन-दर्शन का प्रतीक है, जहां राष्ट्रभक्ति केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और सेवा का रूप ले लेती है।

वंदे मातरम् की रचना अपने आप में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। जब ब्रिटिश शासन भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का प्रयास कर रहा था, तब बंकिमचंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को स्थान दिया। आनंद मठ के संन्यासी यह गीत गाते थे। यह 'संन्यासी विद्रोह' की प्रेरणा बना, जिसने ब्रिटिश सत्ता के सामने भारतीय आत्मबल का पहला प्रतिरोध खड़ा किया। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने सन् 1875 में जब इस गीत की रचना की, तब उन्होंने केवल काव्य नहीं लिखा, उन्होंने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प किया। सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम् शस्यश्यामलाम् मातरम् की पंक्ति ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठे।

सन् 1905 के बंग-भंग आंदोलन के समय वंदे मातरम् एक गीत नहीं रहा। इसकी गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी, जहां स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी के तख्ते पर चढ़ते क्रांतिकारियों के होंठों पर अंतिम उच्चारण भी 'वंदे मातरम्' ही था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया, तो यह केवल गीत नहीं रहा, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गया। वंदे मातरम् ने धर्म और देशप्रेम को एक सूत्र में बांधा, जिससे भक्ति और देशभक्ति एक ही धारा बनकर बहने लगीं। इसी भावधारा ने लाखों भारतीयों को उस स्वाधीनता यज्ञ में आहुति बन जाने की प्रेरणा दी, जिसकी लौ से भारत ने स्वतंत्रता का सवेरा देखा।

स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने भी इस गीत को राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक माना। यही कारण है कि वंदे मातरम् आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए श्रद्धा और गर्व का विषय है। यह गीत कालातीत है, क्योंकि इसमें न तो किसी युग का बंधन है, न किसी प्रदेश की सीमा। इसमें उस भारतमाता की दिव्यता झलकती है, जो केवल भूभाग नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति व सनातन चेतना का जीवंत रूप है। आज जब हम वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का पावन अवसर मना रहे हैं, यह केवल स्मरण का नहीं, बल्कि आत्मावलोकन का क्षण भी है। क्या हम उस भाव को जी पा रहे हैं, जिसके लिए असंख्य देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी? क्या हम अपने जीवन में वही समर्पण, वही अनुशासन और वही मातृभूमि-भक्ति स्थापित कर पाए हैं?

दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वंदे मातरम् पर प्रश्नचिह्न लगाने का साहस करते हैं। कभी इसे सांप्रदायिक कहकर सीमित करने का प्रयास किया जाता है, तो कभी इसे किसी संप्रदाय विशेष से जोड़कर उसकी सार्वभौमिकता को संकुचित किया जाता है। यह प्रवृत्ति न केवल अज्ञान और ऐतिहासिक विस्मृति की उपज है, बल्कि राष्ट्रभावना व सांस्कृतिक एकता के प्रति गहरे अनादर का प्रतीक भी है।

वस्तुतः वंदे मातरम् किसी मत, पंथ या संप्रदाय का गीत नहीं, यह संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। इसमें उस मातृभूमि की वंदना है, जिसकी कृपा से हम सब अस्तित्व पाते हैं। यही कारण है कि 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं था, इस सत्य का प्रतिपादन भी था कि वंदे मातरम् भारतीय राष्ट्र की एकात्म चेतना, श्रद्धा व स्वाभिमान का अमर प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, 'वंदे मातरम् के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्रप्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम् में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं।'

आज भारत आत्मनिर्भरता और विकास की नई यात्रा पर अग्रसर है। इस यात्रा की मूल प्रेरणा वही है, जो डेढ़ शताब्दी पूर्व बंकिमचंद्र ने दी थी, मातृभूमि पर गर्व करने की भावना और कर्म को सेवा में बदलने की भावना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब देश 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तब वंदे मातरम् उस एकता की भावना को और गहराई देता है। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, उसके लोक-जीवन, भाषाओं और संस्कृतियों के समन्वय में है।

वंदे मातरम् का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनाएंगे। जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, सैनिक सीमा पर डटा रहता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार बोता है और युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब 'वंदे मातरम्' अपने सार्थक रूप में जीवित रहता है। आज की युवा पीढ़ी को इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तकनीकी युग की तेज रफ्तार में भी यदि उसके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य का संकल्प बना रहे, तभी यह गीत अमर रहेगा।

आज जब हम इस गीत की 150 वर्षों की यात्रा को नमन करते हैं, तो यह केवल एक साहित्यिक उपलब्धि का सम्मान नहीं, बल्कि उस राष्ट्र-चेतना के स्रोत का अभिनंदन है, जिसने भारत को भारत बनाया। यह गीत हमें सिखाता है कि राष्ट्रप्रेम कोई उत्सव नहीं, वह नित्य आराधना है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत में सफल नहीं हो पाए घरेलू सोशल मीडिया ऐप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामले में देश अब भी संघर्ष कर रहा है। हाइक और कू जैसे ऐप लॉन्च किए गए, लेकिन ये लंबे समय तक टिक नहीं पाए। इसकी वजहें कम निवेश फंडिंग, कमजोर प्रचार और नवाचार की बजाय नकल पर निर्भरता मानी गईं। स्वदेशी-टिकाऊ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना भारत के लिए अब भी एक कठिन चुनौती बना हुआ है। पुनीत कुमार अरोड़ा और जयदीप मुखर्जी की रिपोर्ट...

चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर

दुनिया भर में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लगभग 5.5 अरब लोगों में से करीब 49.1 करोड़ उपयोगकर्ता भारत में हैं। भारतीय रोजाना औसतन 2 घंटे 26 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अमेरिका में 2 घंटे 18 मिनट, चीन में 1 घंटा 56 मिनट, ब्रिटेन में 1 घंटा 49 मिनट आदि बिताते हैं। देश की इंटरनेट आबादी अब एक अरब के करीब पहुंच चुकी है।

■ हाइक, कू जैसे भारतीय ऐप आए, पर टिक नहीं पाए

इन देशों में सबसे ज्यादा यूजर (2024)

देश	यूजर (करोड़ों में)
चीन	106
भारत	49.1
अमेरिका	23.9
ब्राजील	14.4
इंडोनेशिया	13.9
रूस	10.6
जापान	9.6
मैक्सिको	09
फिलीपींस	8.7
वियतनाम	7.3

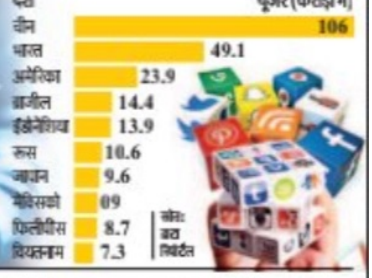

स्रोत: डाटा रिपोर्टल

जहां पहले से ज्यादा लोग, वहीं जुड़ना पसंद

लोग वहीं जुड़ना पसंद करते हैं जहां पहले से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पहले से ही आपस में जुड़े हुए यूजर मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म बदलने से लोगों को अपने दोस्तों और समुदायों को छोड़ना पड़ता है इसलिए भारतीय ऐप के लिए इस नेटवर्क को तोड़ पाना मुश्किल है।

नए फीचर्स से जोड़े रखते हैं

कू को एक्स का विकल्प माना गया था। हाल ही में, जोहो कंपनी के अरत्तई मैसेजर ऐप में सरकार के डिजिटल आत्मनिर्भरता अभियान के बाद तेजी से डाउनलोड बढ़े। वैश्विक प्लेटफॉर्म लगातार नए फीचर और बेहतर अनुभव देकर अपने उपयोगकर्ताओं को जोड़े रखते हैं।

स्थानीय भाषा में देखना पसंद

भारत के लगभग 98% इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री देखते या पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी लगभग 57% उपयोगकर्ता स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हैं।

Hindustan Page No-15